

संक्षिप्त

अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चोरी

गोंदिया : शहर थाने के तहत सिविल लाइन्स निवासी फ़ियादी अंकीत सुधीर शहारे (34) अपनी जुपीटर मोटरसाइकिल से बीजीडब्ल्यू शासकीय महिला अस्पताल गया था. उसने अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल परिसर में रखा था. जिसे अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. जिसकी कीमत 20 हजार रु. बताई गई है. फ़ियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

सोने-चांदी के आभूषण चोरी

गोंदिया : ग्रामीण थाने के तहत साई माऊली कॉलोनी निवासी फ़ियादी दीक्षा गुणरामसाद नागपुरे (30) के घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने लोहे की अलमारी से 56 हजार 600 रु. कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिया. फ़ियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

जहर पीने से हुई मौत

गोंदिया : देवरी थाने के तहत लोहारा निवासी रमेश भुरेसिंग बैस (54) ने जहर पी लिया. उसे ग्रामीण अस्पताल देवरी में ले जाया गया. जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. निशांत बैस (23) की शिकायत पर देवरी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है.

जंगली सूअर व बंदरों से परेशानी

गोरेगांव : आए दिन ग्रामीण क्षेत्र के अनेक गांवों में बंदरों व सूअरों का आतंक बढ़ने से खेती करना मुश्किल होते जा रहा है. जंगली जानवर किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं. गांवों में बंदरों व जंगली सुअरों का आतंक काफी बढ़ गया है.

बस सेवाओं को लेकर छात्र परेशान

गोरेगांव : तहसील के डिमरटोली-डब्बा में स्थित छात्र बस सेवाओं को लेकर परेशान हो रहे हैं. यहां बड़ी संख्या में छात्र गोरेगांव शहर प्रतिदिन आवागमन करते हैं. लेकिन बसों की कमी छात्रों के लिए परेशानी बन रही है. उल्लेखनीय है कि डिमरटोली बस स्टॉप पर सुपर फास्ट बसे रुकती नहीं और सर्वसाधारण बसें बहुत कम चलती हैं. ऐसे में डब्बा-डिमरटोली, तुमखेडा, गणखैरा से आवागमन करने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

करंट लगने से बालक झुलसा

गोंदिया : आमगांव तहसील अंतर्गत ग्राम करंजी निवासी 11 वर्षीय दिव्यांशुलक्षण बागडे विद्युत करंट लगने से झुलस गया. उसे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में भर्ती कराया गया.

20 हजार की घूस लेते वनपाल रमेश पचारे रंगेहाथ दबोचा

दो वनरक्षक भी हिरासत में ; रेत उत्खनन व परिवहन मामले में कार्रवाई नहीं करने के एवज में मांगी थी 25 हजार की रिश्त

संवाददाता / गोंदिया

रेत उत्खनन एवं परिवहन के मामले में कार्रवाई नहीं करने के एवज में 20 हजार रुपए की रिश्त स्वीकार करते हुए वन विभाग के एक वनपाल को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) की टीम ने मंगलवार, 11 अगस्त को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अर्जुनी मोरगांव तहसील के गोठणगांव वनपरिक्षेत्र अंतर्गत पारसटोला क्षेत्र में की गई। इस मामले में वनपाल के साथ दो वनरक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के बाद वन विभाग में खलबली मच गई है। गिरफ्तार वनपाल की पहचान रमेश खारामपचारे (57) के रूप में हुई है। वह राजुली सावनक्षेत्र, गोठणगांव वनपरिक्षेत्र में वनपाल के पद पर कार्यरत है। उसके साथ वनरक्षक निलोत्पल हीरालाल शिकारे (31) व चिंटू मंगलसिंह परिहार (38) को भी एसीबी ने



हिरासत में लिया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के घर का निर्माण कार्य चल रहा है। मार्च 2026 में निर्माण कार्य के लिए नाले से रेत लाते समय वनपाल रमेश पचारे ने शिकायतकर्ता का ट्रैक्टर रोक लिया था। इस दौरान रेत उत्खनन एवं परिवहन के मामले में कार्रवाई करने की धमकी देते हुए कार्रवाई से बचाने के एवज में कथित तौर पर 25 हजार रुपए की रिश्त की मांग की

गई थी।

इसके बाद 9 जुलाई को शिकायतकर्ता रॉयल्टी की रेत घर पहुंचाकर खाली ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान वनपाल पचारे और वनरक्षक निलोत्पल शिकारे ने उसका ट्रैक्टर रोककर चाबी निकाल ली। आरोप है कि इस दौरान भी दोनों ने रुपए की मांग की और रकम नहीं देने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी।

पारसटोला राउंड कार्यालय में उपस्थित रहने का नोटिस दिया

5 अगस्त को वनपाल पचारे ने शिकायतकर्ता को 8 अगस्त को पारसटोला राउंड कार्यालय में उपस्थित रहने का नोटिस दिया। शिकायतकर्ता निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि वहां वनपाल पचारे और वनरक्षक शिकारे ने मामले को 'सेटलमेंट' करने की बात कही। इसके बाद 25 हजार रुपए की बजाय 20 हजार रुपए देने की मांग की गई। रिश्त देने की इच्छा नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने 10 अगस्त को गोंदिया स्थित एसीबी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। एसीबी ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू की। 11 अगस्त को एसीबी टीम ने पंचों की उपस्थिति में शिकायत की पुष्टि की। शिकायतकर्ता को वॉइस रिकॉर्डर उपलब्ध कराकर पंचों के साथ संबंधित वन अधिकारियों के कार्यालय भेजा गया। इस दौरान वनपाल रमेश पचारे, वनरक्षक निलोत्पल शिकारे और चिंटू परिहार की मौजूदगी में शिकायतकर्ता के खिलाफ रेत उत्खनन एवं परिवहन के मामले में कार्रवाई नहीं करने के बदले 20 हजार रुपए की रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। शिकायतकर्ता को रिश्त की रकम लेकर संबंधित कार्यालय में भेजा गया। जैसे ही वनपाल रमेश पचारे ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपए स्वीकार किए, पहले से तैयार एसीबी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। रिश्त स्वीकार किए जाने के दौरान मौके पर मौजूद वनरक्षक निलोत्पल शिकारे और चिंटू परिहार को भी एसीबी टीम ने हिरासत में लिया। तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई एसीबी के पुलिस उपअधीक्षक निलेश लोधी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक उमाकांत उगले, अरविंद राजूत की टीम ने की।



दिल्ली में कर्मचारियों की महारैली समय की मांग

संवाददाता / गोंदिया

महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक नांदेड़ जिला परिषद नांदेड़ के यशवंतराव चव्हाण सभागृह में राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले की अध्यक्षता तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत जामोदे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई. बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित सेवा संबंधी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. गोंदिया जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए महासंघ के उपाध्यक्ष कमलेश बिसेन ने 7, 8 व 9 सितंबर 2018 को की गई वेतन कटौती की भरपाई देने, गोंदिया को आदिवासी जिला घोषित करने, संविदा ग्राम



पंचायत अधिकारियों का मानधन सेवार्थ आईडी के माध्यम से देने, अनुकंपा नियुक्तियों को नियमित वेतन पर करने तथा लिपिक वर्ग की वेतन विसंगतियां दूर करने जैसी प्रमुख मांगें मंच से उठाई. इस दौरान राज्य कार्याध्यक्ष एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत जामोदे, राज्य महासचिव संजय महालणकर,

राज्य उपाध्यक्ष कैलास नाना वाघचौरे, सलाहकार अतुल वर्मा, महिला उपाध्यक्ष कविता बोंदे, गोंदिया जिले से उपाध्यक्ष कमलेश बिसेन तथा महासचिव संतोष तोमर समेत राज्य के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में राज्य भर के कर्मचारी संगठनों के लंबित मुद्दों,

संगठनात्मक कार्यों और भविष्य की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान विभिन्न पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया. समापन अवसर पर राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले ने 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली कर्मचारी महारैली को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र से कम से कम 3,000 प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया. कमलेश बिसेन ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए सभी कर्मचारियों का एकजुट होकर दिल्ली पहुंचना समय की आवश्यकता है.

सड़क की बदहाली से बंद थी एसटी बस सेवा

संवाददाता / अर्जुनी मोर

अर्जुनी मोरगांव-निलज-मालकनपुर-माहूरकुडा-सिरौली-महागांव-बोरी मार्ग की लंबे समय से बदहाल स्थिति के चलते नागरिकों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण इस मार्ग पर एसटी बस सेवा भी बंद कर दी गई थी. आखिरकार नागरिकों की मांग का सफल लेते हुए जिला परिषद के निर्माण विभाग ने सड़क के गड्ढे भरने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है. 4 अगस्त 2026 को क्षेत्र के ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत और बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर अर्जुनी मोरगांव के उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था. मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद जिला परिषद गोंदिया के अध्यक्ष लायक राम भेंडारकर तथा विधायक इंजि. राजकुमार बडोले के विशेष प्रयासों से सड़क मरम्मत का काम शुरू



किया गया है. विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़क की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था. इसके चलते एसटी महामंडल ने इस मार्ग पर बस सेवा बंद कर दी थी. बस सेवा बंद होने का सबसे अधिक असर स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर पड़ा. सड़क की तत्काल मरम्मत कर बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन देकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था.

तिरोड़ा क्षेत्र में रानडुकरों का बढ़ता आतंक; वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग

नगराध्यक्ष अशोक असाटी ने वन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता / तिरोड़ा

तिरोड़ा क्षेत्र में रानडुकरों की बढ़ती संख्या से किसानों एवं ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही रानडुकरों के कारण ग्रामीणों की सुरक्षा का प्रश्न भी गंभीर होता जा रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर तिरोड़ा नगराध्यक्ष अशोकजी असाटी सहित जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में नगराध्यक्ष अशोकजी असाटी, शिक्षण सभापति देवेन्द्र तिवारी, नगरसेवक अनिकेत कटरे, रविरेकर, शीतल तिवड़े एवं मौनू भुते ने तिरोड़ा के वन अधिकारी भगत को ज्ञापन



सौंपकर रानडुकरों के बढ़ते आतंक पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र में रानडुकरों की संख्या लगातार बढ़ने से किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में रानडुकरों के झुंड पहुंचने से किसान रात के समय भी अपनी फसलों की रखवाली करने

के लिए मजबूर हैं। इससे किसानों में भय और असुरक्षा का वातावरण निर्माण हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग से रानडुकरों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं दीर्घकालीन उपाय करने, संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने तथा किसानों की फसलों और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

स्वतंत्रता दिवस पर सजेगी सुरों की महफिल

संवाददाता / □

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना को समर्पित विशेष संगीतमय कार्यक्रम 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' का आयोजन 15 अगस्त को शाम 5 बजे स्थानीय मधुराज लॉन में किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन कलासागर संस्था की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में देशभक्ति एवं सांस्कृतिक गीतों की सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भावना को स्वर दिया जाएगा।

कराओ के संगीत प्रणाली पर आधारित इस आयोजन में शहर के महिला एवं पुरुष संगीतप्रेमियों के साथ ही आम नागरिक भी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर सकेंगे। आयोजन का उद्देश्य संगीत के माध्यम से राष्ट्रप्रेम,

एकता और सांस्कृतिक सौहार्द की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। विशेष बात यह है कि कार्यक्रम में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। इससे शहर के नागरिकों तथा गायन एवं संगीत के शौकीनों को स्वतंत्रता दिवस की संस्था को देशभक्ति के रंग में रंगने का अवसर मिलेगा। यह संगीतमय आयोजन कलासागर संस्था द्वारा विदर्भ साहित्य संघ, लायंस क्लब पावरसिटी, लोकमत सखी, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ एवं पतंजलि आरोग्य केंद्र के विशेष सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने तिरोड़ा शहर एवं आसपास के नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने तथा देशभक्ति से ओतप्रोत इस संगीतमय संस्था का आनंद लेने का आह्वान किया है।

वडेगांव में डायरिया का प्रकोप नियंत्रण में स्वास्थ्य अधिकारी ने किया दौरा

गोंदिया : देवरी तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ला अंतर्गत वडेगांव में दूषित पानी के कारण डायरिया का प्रकोप सामने आया था. 6 अगस्त से गांव में डायरिया के मरीज मिलने लगे थे. पांच दिनों में कुल 45 लोग इस बीमारी की चपेट में आए. स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई और ग्राम पंचायत के सहयोग से अब स्थिति नियंत्रण में है.

सभी 45 मरीजों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजीत गोल्हार के मार्गदर्शन में मुल्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य टीम को 6 अगस्त से वडेगांव में तैनात किया गया है. टीम की ओर से संक्रमित मरीजों का उपचार करने के साथ ही



संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजीत गोल्हार ने वडेगांव पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही उपचार व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानकारी ली. इस दौरान जिला संक्रामक रोग अधिकारी डा. निरंजन अग्रवाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ला के चिकित्सा अधिकारी डा. वंजारी व डा. रामकृष्ण येडने आदि उपस्थित थे.

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मुंडीकोटा-तिरोड़ा विशेष बस सेवा शुरू करने की मांग

जिला परिषद सदस्य किरणकुमार पारधी ने तुमसर आगार प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता / तिरोड़ा

मुंडीकोटा ग्राम पंचायत क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए मुंडीकोटा-तिरोड़ा मार्ग पर विशेष बस सेवा शुरू करने की मांग की गई है। इस संबंध में तुमसर आगार के व्यवस्थापक सचिन आगरकर, राहुल बोरसे तथा यंत्र अभियंता सतीश कटरे से प्रत्यक्ष भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया।

मुंडीकोटा ग्राम पंचायत क्षेत्र के बड़ी संख्या में विद्यार्थी तिरोड़ा स्थित एसडीबी विद्यालय में शिक्षा



प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय तक नियमित और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्रतिदिन आवागमन में अनेक कठिनाइयों का सामना

करना पड़ रहा है। कई विद्यार्थियों को निजी साधनों अथवा अन्य वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनके समय और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है।

इसी पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित, सुविधा और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता देते हुए मुंडीकोटा-तिरोड़ा विशेष बस सेवा तत्काल शुरू करने की मांग प्रतिनिधिमंडल की ओर से की गई। बस सेवा शुरू होने से मुंडीकोटा सहित आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य किरणकुमार पारधी, सरपंच तुरीन भाऊ नागपुरे तथा कमलेश पारधी उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल ने आगार प्रशासन से विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। इस संबंध में प्रतिनिधियों ने कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा, सुरक्षित यात्रा और उच्चलभ्य के लिए आवश्यक प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। अब विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजर परिवहन विभाग द्वारा इस मांग पर की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

बिजली बिलों ने बढ़ाई मुसीबत

उपभोक्ताओं में रोष, बिना एसी-कूलर वाले घरों में भी 5 हजार के बिल

संवाददाता / गोरेगांव

महावितरण के बढ़ते विद्युत बिलों ने आम नागरिकों की आर्थिक परेशानी बढ़ा दी है. पिछले मार्च, अप्रैल, मई और जून माह में हजारों रु. के बिजली बिलों का भुगतान करने के बाद अब जुलाई में भी कई उपभोक्ताओं को 4 से 5 हजार रु. तक के बिल थमाए गए हैं.

कूलर जैसी बिजली की अधिक खपत करने वाली सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं, उन उपभोक्ताओं को भी भारी-भरकम बिल मिलने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली की खपत और बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है.



नागरिकों का कहना है कि जितनी बिजली वास्तव में खर्च नहीं होती, उससे कहीं अधिक यूनिट बिल में दिखाई जा रही हैं. इसके कारण सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरेलू बजट पर भारी असर पड़ रहा है. भुगतान नहीं तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई एक ओर उपभोक्ता बड़े हुए बिलों को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर

महावितरण की ओर से बिल वसूली के लिए लगातार फोन किए जा रहे हैं. तारीख तक बिल का भुगतान नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क भी उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है. ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे नागरिकों की परेशानी और बढ़ गई है.



संपादकीय

पैलेट के जख्म

इसमें दो राय नहीं कि किसी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के किन्हीं परिस्थितियों में उग्र होने और जन-धन की हानि रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। इसमें भी दो राय नहीं है कि राज्य के पास हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध को रोकने के लिए प्रयोग की गई ताकत का स्तर क्या रहा। जाहिर है राफ़्टिविरोधी ताकतों, हिंसक भीड़ तथा छात्रों के आंदोलन को एक ही तौर-तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। इसी आलोक में सवाल पैदा होता है कि जंतर-मंतर से शुरूहुए संसद चलो मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई ताकत क्या जरूरी थी? क्या उचित तरीके से अधिकृत थी? ऐसा ही विवाद इस आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर खड़ा हुआ है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया। जबकि बाद में जनरल डायरी में यह दर्ज किया गया कि रैंपिड एक्शन फोर्स में एंटी-रायट गन से दो राउंड फायरिंग की थी। वहीं दूसरी ओर छात्र प्रदर्शनकारियों पर बलप्रयोग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। खासकर, कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने गृह मंत्री पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। वे बाकायदा गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली के दो अस्पतालों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार बीस जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम दस लोगों को पैलेट गन से चोट लगी थी। इन अस्पतालों में पैलेट गन से आहत छात्रों ने उपचार कराया था। निस्संदेह, पैलेट गन से घायल होने वालों का यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, न कि किसी बिना पुष्टि वाले दावों पर आधारित है।

दरअसल, पैलेट गन की जद में आये छात्रों के अनुभव परेशान करने वाले रहे हैं। खबरों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों के चेहरों, छाती और आंखों पर चोट आई है। आंशकां व्यक्ति की जा रही है कि एक छात्र की आंख की रोशनी भी जा सकती है। सार्वजनिक विमर्श में सवाल उठाये जाते रहे हैं कि छात्र आंदोलनकारियों के विरुद्ध पैलेट गन का इस्तेमाल करने का तार्किक आधार क्या है। वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के दौरान मेटल पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हथियार रखने की कानूनी वैधता और किसी खास घटना में इनके गलत इस्तेमाल के आरोपों के बीच फर्क किया है। निस्संदेह, इस फर्क की सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। इसके इस्तेमाल के बाद किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए स्थिति को साफ करने के लिए पारदर्शिता अपनाना भी बेहद जरूरी है। इससे जुड़े कई तथ्यों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए, जिसमें गोला-बारूद का पर्याप्त रिकॉर्ड रखना, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस की बातचीत का रिकॉर्ड और साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। साथ ही इन तथ्यों की स्वतंत्र जांच की जानी भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकार का भी दावित बनता है कि भीड़ को काबू करने में पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े तमाम नियम स्पष्ट रूप से बताए जाएं। वहीं दूसरी ओर यदि इनका अंधाधुंध प्रयोग किया गया हो तो इसके लिये जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना भी बेहद जरूरी है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में विरोध करने का अधिकार एक घोषित संवैधानिक स्वतंत्रता है। इसकी रक्षा के लिए संयम की जरूरत अपरिहार्य शर्त है। यह दोनों तरफ से जरूरी है- प्रदर्शनकारियों और सरकार की तरफ से। लेकिन विद्वाना है कि अक्सर देश में पुलिस व सुरक्षाबल छात्रों के धरनों व प्रदर्शनों के दौरान बात-बात पर निर्ममता से लाठी भांजते नजर आते हैं।

अनधिकृत इमारत, मॉल, अस्पताल पर होगी कार्रवाई

आज से विशेष मुहिम । अवैध निर्माण पर गिरेगी गाज

नागपुर : शहर में अनधिकृत तरीके से किए गए निर्माण, अवैध गोदाम, अनधिकृत उपयोग व अग्निशमन नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ मनपा सख्त रुख अपनाने के मूढ़ में है. हर जोन में दस मामलों को चिन्हित किया गया है. ऐसे में १०० मामलों में कार्रवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मनपा के विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय स्थापित कर जोन कार्यालयों की मदद से कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. महापौर नीता ठाकरे के निर्देशानुसार शहर के सभी दस जोन में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वाले खतरनाक प्रतिष्ठानों के खिलाफ गुरुवार १३ अगस्त से कार्रवाई करने वाली है.

नागपुर शहर में अनधिकृत निर्माण ,



मंजूर नक्शे के बिना किए गए निर्माण, अनधिकृत उपयोग परिवर्तन, अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक प्रतिष्ठानों तथा अतिक्रमण के मामलों में संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए महापौर नीता ठाकरे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर, स्थापत्य समिति सभापति अश्विनी जिचकार, अग्निशमन समिति की सभापति रुपाली ठाकुर, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अंकित, अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त मंगेश खवले, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके आदि उपस्थित थे.

अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा से जुड़े इंतजाम नहीं करने वाले इमारतों व प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर जोन कार्यालयों के सुपुर्द कर दिया है. संबंधित कार्रवाई के दायरे में अवैध निर्माण करने वाले मॉल एवं व्यावसायिक परिसर, अस्पताल, शोरूम, गोदाम, अस्थायी स्वरूप के शेड/पेंडाल संरचनाएं, ट्यूशन क्लासेस, बार एवं रेस्टोरेंट, अनधिकृत उपयोग वाली इमारतों

सील होंगे इमारत , मॉल

नगर रचना विभाग ने हर जोन में स्वीकृत निर्माण अनुमतियों और वास्तविक उपयोग की जोनवार अद्यतन सूची उपलब्ध कराई है. यदि स्वीकृत नक्शे के विपरीत किसी भवन या प्रतिष्ठान का वास्तविक उपयोग किया जा रहा है, तो तत्काल कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. इमारत को सील भी किया जाएगा. पिछले दिनों शोरूम के अनधिकृत उपयोग के मामले में एक इमारत को सील भी किया गया. महीने भर चलेगा विशेष अभियान : यह विशेष अभियान १३ अगस्त से शुरू होकर ८ सितंबर २०२६ तक लक्ष्य भूभाग एक महीने की अवधि में प्रभावी रूप से चलाया जाएगा. हर जोन द्वारा चुने गए १० मामलों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है. इसमें प्रतिष्ठान का नाम, मालिक व अन्य जानकारी देनी होगी.

तथा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

संयुक्त दल करेगा कार्रवाई

इससे पहले विभिन्न विभागों की तरफ से अलग-अलग की जाने वाली कार्रवाई को रोककर अब सभी संबंधित विभाग आपसी

समन्वय स्थापित करते हुए ‘संयुक्त दल’ बनाकर कार्रवाई करेंगे. इसमें अग्निशमन विभाग, संबंधित जोन कार्यालय, प्रवर्तन विभाग, उपद्रव खोज दल, नगररचना विभाग और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाएंगे.

युवती से मारपीट और अश्लील हरकत का आरोप

संवाददाता । नागपुर

एमआईडीसी थाने के तहत २२ वर्षीय युवती के साथ मारपीट, कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर उसके रिश्तेदार युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी हिंगणा निवासी सूरज नेताम (२६) है.

पुलिस के अनुसार आरोपी सूरज और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे. शिकायत में दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद से उससे संपर्क नहीं रखा. १० अगस्त को आरोपी उसके किराए के कमरे पर पहुंचा. उसके साथ बातचीत नहीं करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.

आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इसके बाद चाकू का डर दिखाकर उसके कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया. एमआईडीसी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

आशा , गुटप्रवर्तक का जिला परिषद के सामने प्रदर्शन



चंद्रपुर : आशा कार्यकर्ता, गुट प्रवर्तक, शालेय पोषणाहार कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं तथा कृषि मित्रों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आयटक के नेतृत्व में सोमवार को चंद्रपुर जिला परिषद कार्यालय के सामने जोरदार आंदोलन किया गया. आजाद बगीचा से मोर्चा निकालकर जिला परिषद के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया. इसके बाद जेल भरो आंदोलन तथा करीब एक घंटे तक रास्ता रोको आंदोलन किया गया.

आंदोलनकारियों ने न्यूनतम वेतन व मानदेय में बढ़ोतरी, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेयुटी, पीएफ, दिवाली बोनस तथा नियमित मानदेय देने की मांग की. शालेय

पोषणाहार कर्मचारियों का बकाया मानदेय तत्काल अदा कर उन्हें जिला परिषद सेवा में स्थायी करने तथा न्यूनतम वेतन के अनुसार २६ हजार रु. मासिक वेतन देने की मांग भी की गई.

आंदोलन का नेतृत्व आयटक के राज्य सचिव विनोद झोड़े पाटिल, राजू गैनवार, रवींद्र उमाटे सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने किया. आंदोलन के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया.

आंदोलन में जिले भर के आशा, गुट प्रवर्तक, पोषणाहार कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका तथा कृषि मित्र बड़ी संख्या में शामिल हुए.

डॉक्टरों की कमी से पड़ोसी राज्य भाग रहे मरीज

सिरोंचा ग्रामीण अस्पताल: करोड़ों के उपकरण धूल फांक रहे,

सिरोंचा : सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए सिरोंचा के ग्रामीण अस्पताल में करोड़ों रुपये खर्च कर अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर और मेडिकल उपकरण तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती करना भूल गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में ये महंगे उपकरण सिर्फ शो-पीस बनकर रह गए हैं।

इसका सबसे बड़ा खामियाजा गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। आपात स्थिति में प्रसूति (डिलीवरी) के समय महिलाओं को इलाज के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भूपायपल्ली और मंचेरियाल स्थित अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

दुर्गम क्षेत्र होने से कतरा रहे विशेषज्ञ

प्रशासनिक सूत्रों के



मुताबिक, सिरोंचा क्षेत्र काफी दुर्गम और आदिवासी बहुल है। इस वजह से विशेषज्ञ डॉक्टर यहां अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते। स्थानीय लोगों की मांग है कि मंत्रालय स्तर पर इसके लिए कोई विशेष नीति बनाई जाए ताकि डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति हो सके। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद केवल डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को १०० किलोमीटर दूर दूसरे राज्य के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

चीज एनालॉग पर ‘एफडीए’ की कार्रवाई

२३ हजार किलो स्टॉक नष्ट, अजित डिलाइट का ९.८२७ किलो टोस्ट जब्त

नागपुर : प्रतिबंधित चीज एनालॉग के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने नागपुर में बड़ी कार्रवाई की। शहर की दो डेयरी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चीज एनालॉग और दुग्धजन्य पदार्थों का स्टॉक जब्त किया गया। करीब ४६ लाख रुपये कीमत का २३ हजार किलो चीज एनालॉग और दही नष्ट किया गया। वहीं, बूटीबोरी स्थित मे. अजित डिलाइट प्रा. लि. कंपनी पर लेबलिंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई की गई। यहां १४ लाख १३ हजार ८५४ रुपये कीमत का ९ हजार ८२७ किलो ‘रस्क टोस्ट’ जब्त किया गया है। ‘एफडीए’ के अनुसार, ७ अगस्त को बूटीबोरी के फूड पार्क, फाइन स्टार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मे. अजित डिलाइट प्रा. लि. की जांच की गई। जांच के दौरान कंपनी के ‘रस्क’ उत्पाद के लेबल पर ‘आर्टिफिशियल स्वीटनर

दो डेयरियों पर कार्रवाई

‘सेफ फूड एंड सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत ६ अगस्त को नागपुर शहर की मे. चंद्रा डेयरी, पिपली नदी, वांजरा और मे. शिवम डेयरी फूड प्रॉडक्ट्स, ईटा भट्टी चौक में ‘एफडीए’ की टीम ने जांच की। चंद्रा डेयरी में दही, चीज एनालॉग और स्किम मिल्क पाउडर के नमूने जांच के लिए लिए गए। इसके बाद ४२ लाख ३० हजार ६१० रुपये कीमत का २२ हजार ३५ किलो स्टॉक जब्त किया गया। वहीं, शिवम डेयरी फूड प्रॉडक्ट्स में उत्पादित चीज एनालॉग का नमूना लेने के बाद ४ लाख ६२ हजार ८०० रुपये कीमत का १ हजार ९३० किलो स्टॉक जब्त किया गया। महाराष्ट्र में चीज एनालॉग के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के तहत दोनों प्रतिष्ठानों में मौजूद दही और चीज एनालॉग का स्टॉक नष्ट कर दिया गया।



आई.एन.एस. ९.१’ के इस्तेमाल का उल्लेख मिला। हालांकि, कृत्रिम अथवा ‘नॉन-न्यूट्रिटिव स्वीटनर’ के इस्तेमाल के संबंध में ग्राहकों के लिए जरूरी चेतावनी

लेबल पर नहीं दी गई थी।

नियमों के अनुसार, लेबल पर ‘दिस कंटेस’ (कृत्रिम/नॉन-न्यूट्रिटिव स्वीटनर का नाम) के साथ ‘नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन’ की घोषणा करना जरूरी है। ‘एस्पार्टेम’ का इस्तेमाल होने पर ‘नॉट फॉर फिनाइल की टोन्यूरिक्स’ देना भी अनिवार्य है। इन घोषणाओं का अभाव पाए जाने पर संबंधित रस्क टोस्ट का स्टॉक जब्त कर लिया गया।

कंटेनर चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस

मामला समृद्धि पर हंगामा मचाने का

वर्धा : नेशनल परमिट होने के बावजूद चालान काटने से नाराज कंटेनर चालक, समृद्धि महामार्ग पर कंटेनर को आड़ा करके फरार हो गया। सावंगी मेघे पुलिस ने इस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। चालक की इस करतूत के चलते समृद्धि महामार्ग पर लंबा जाम लगने से आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ी।

नौ अगस्त को समृद्धि महामार्ग पर गणेशपुर में उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, वर्धा के अधिकारियों का उड़न दस्ता वाहनों की जांच कर रहा था। इसी दौरान दस्ते को नागपुर से मुंबई जा रहा कंटेनर क्र. एचआर ५५/बीए ८५४४ ‘नो पार्किंग’ में खड़ा मिला।

कंटेनर चालक राजूलाल बलाई ने दस्तावेज मांग रहे आरटीओ टीम से विवाद किया। आरटीओ ने ई-चालान मशीन से दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि कंटेनर नेशनल परमिट वाला है। इसके



बाद चालक से टैक्स रसीद मांगी गई तो पता चला कि चालक नागपुर से माल लेकर मुंबई जा रहा है। यह बात नियमों का उल्लंघन होने के कारण आरटीओ ने चालान बना दिया। इससे नाराज चालक ने अपना कंटेनर बीच सड़क में खड़ा करके चाबी लेकर फरार हो गया। इस वजह से महामार्ग पर वाहनों की कतार लज गई।

घटना की जानकारी मिलते ही महामार्ग पुलिस, जाम में तैनात पीएसआई सरिता यादव अपनी टीम के साथ पहुंची और चालक राजूलाल बलाई को पकड़ा गया। घटनास्थल पर आने के बाद भी वह कंटेनर हटाने को तैयार नहीं था, न ही वह चाबी दे रहा था। ऐसे में जबरन चाबी छीनकर कंटेनर

हटाया गया। यातायात सुचारु करने में सावंगी मेघे के थानेदार विनोद गिरि, पीएसआई मनोज टिपले, श्याम सलामे की टीम ने मदद की। चालक पर धारा ११०, १२१ (१), १२६ (२), १३२, २२१, २८५ बीएनएस सह धारा ८(ब) राष्ट्रीय राजमार्ग कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल रवाना किया गया। प्रभारी आरटीओ अधिकारी संदीप मुखे ने बताया कि नेशनल परमिट धारक एक राज्य से दूसरे राज्य में ही माल परिवहन कर सकता है। इस मामले में चालक माल नागपुर से मुंबई लेकर जा रहा था अतः कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की गई।

सदर पुल पर कार ने लोको पायलट को कुचला , मौत

आरोपी वाहन चालक फरार, सहकर्मी ने पहुंचाया अस्पताल

नागपुर : सदर पुल पर हल्दीराम के पास सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में सेंट्रल रेलवे के लोको पायलट की मौत हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोको पायलट को उनके सहकर्मी ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद सफेद रंग की कार का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान इंद्रजीत सरकार (५१) के रूप में हुई है। वे शंभुनगर, तिरंगा चौक क्षेत्र में रहते थे और सेंट्रल रेलवे, नागपुर में लोको पायलट के पद पर कार्यरत थे।

पुलिस में दर्ज शिकायत के

अनुसार, शिकायतकर्ता परितोष कुमार संजय कुमार भी सेंट्रल रेलवे के अजनी इलेक्ट्रिक लोको शेड में कार्यरत हैं। सोमवार को रात १२ बजे से सुबह ८ बजे तक ड्यूटी पूरी करने के बाद वे अपनी कार से घर लौट रहे थे। सुबह करीब ८.१५ बजे सदर फ्लाईओवर पर हल्दीराम के पास उन्हें सड़क पर एक दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर घायल व्यक्ति की पहचान उनके सहकर्मी इंद्रजीत सरकार के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने पर पता चला कि सफेद रंग की कार क्रमांक एमएच-३१ डीसी-२६३० ने दोपहिया वाहन

को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद चालक छावनी की ओर वाहन लेकर फरार हो गया।

परितोष ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से इंद्रजीत सरकार को अपनी कार से मानकापुर चौक स्थित मैक्स अस्पताल पहुंचाया। उन्हें सुबह करीब ८.२६ बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उपचार शुरू करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक शुभांगी मायटक कर रही हैं।

नागपुर : महानगरपालिका के प्रवर्तन विभाग ने सोमवार १० अगस्त को काछीपुरा, पूर्व शंकर नगर, धरमपेट, सीताबर्डी, महाल, बड़कस चौक, आईटी पार्क और वीएनआईटी परिसर में संयुक्त अभियान चलाकर सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई धरमपेट जोन के तहत काछीपुरा, पूर्व शंकर नगर में कॉर्नर हाउस दाबा की ओर जाने वाले मार्ग, अपना दाबा एवं एनएच-१ की ओर जाने वाले मार्ग, जगदीश सावजी के पास तथा साईं वाटिका की ओर जाने वाले मार्ग पर नाले के ऊपर बनाए गए चार अवैध स्लैब निर्माणों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया।

मनपा अधिकारियों के अनुसार, इन



आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए स्लैब हटाने नाले को पूरी तरह मुक्त कराया गया। इस दौरान साईं वाटिका नामक लॉन के संचालक विजय तालेवार द्वारा दस्ते के अधिकारियों के साथ बहस हुई। आरोप है कि तालेवार ने गाली-गलौज कर कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया। जिसके बाद स्थिति को

सीताबर्डी में मेन रोड से वैरायटी चौक तक मुहिम

सीताबर्डी इलाके में सीताबर्डी मेन रोड से वैरायटी चौक तक तथा वापस सीताबर्डी मेन रोड, वीएनआईटी-आईटी पार्क और अन्य इलाकों में दिन भर कार्रवाई जारी रही। इस दौरान सड़क के दोनों ओर रोड और फुटपाथ पर लगाए गए अवैध ठेले तथा अनधिकृत दुकानें हटाई गईं। दूसरी टीम ने महाल इलाके में महाल चौक से बड़कस चौक, केलीबाग रोड, गडकरी वाड़ा परिसर, कल्याणेश्वर मंदिर परिसर होते हुए फिर महाल और बड़कस चौक तक कार्रवाई की। इस दौरान सड़क एवं फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों, ठेलों और दुकानों को हटाया गया।

देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

बजाजनगर पुलिस तालेवार को थाने ले गई, जिसके बाद तालेवार को सूचनापत्र देकर छोड़ दिया गया।

अवैध दुकानदारों पर होगी एफआईआर

शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर शिकंजा

कसने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वीएनआईटी रोड, बजाज नगर, सिविल लाइंस, तेलंगखेड़ी, एलएडी कॉलेज और ट्रैफिक पार्क क्षेत्र में फुटपाथ व सड़कों पर अतिक्रमण किए गए हैं। मनपा आयुक्त के निर्देश पर धरमपेट जोने के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में अनधिकृत दुकानों तथा फुटपाथ पर सामान रखने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

आदिवासी दिवस कार्यक्रम डा. अनघा आमटे का प्रतिपादन

कुरमा प्रथा बंद कर मुख्यधारा में आएँ

संवाददाता । भारमरागड
आदिवासी समाज बदलते समयके साथ 'कुरमा प्रथा' को बंद कर विकास की मुख्यधारा में सहभागी बने. साथ ही दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग से बचते हुए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें और प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आए, ऐसा आह्वान डा. अनघा दिगंत आमटे ने किया.

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भारमरागड़ में संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोदुल समिति की ओर से आदिवासी दिवस कार्यक्रम उत्साहपूर्ण एवं शक्तिपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया. भारमरागड़ वन विभाग



के सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत भूमि गायता के हाथों सप्तरंगी ध्वजारोहण से हुई. जिसमें वह अध्यक्ष के रूप में बोल रही थी.

प्रधानाचार्य पदमावार, संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोदुल समिति अध्यक्ष सुरेश पुंगाटी, पुलिस जवान एवं शौर्य पदक प्राप्त योगेंद्र सडमेक समेत एड बंडू आत्राम आदि मान्यवर उपस्थित थे.

डा. अनघा आमटे ने आदिवासी समाज के विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक प्रगति और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की आवश्यकता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, पारंपरिक प्रथाओं में मौजूद कालबाह्य बातों को छोड़कर समाज को विकास की मुख्यधारा में सहभागी होना चाहिए. साथ ही प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर

उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भारमरागड़ तहसील में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान कर उनके योगदान की सराहना की गई. जिनमें तन्वी कुडयामी, रुपेश ताड़ो, देवदास वाचमी, वंदना आलाम, मनीषा मज्जी, पोद्दी कुडयेटी, पालिकराव आलाम, सैन्तू आत्राम, शामराव सडमेक, प्रियंका ओक्सा, ममता सारमपल्लीवार, बंडू आत्राम, योगेंद्र सडमेक, सीताराम मड़ावी, बांगारु गावड़े, चिना महाका आदि का समावेश है. कार्यक्रम का संचालन प्रवीण वडडे ने किया. आभार प्रदर्शन राजू कालंगा ने माना. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोदुल समिति भारमरागड़ के पदाधिकारी और सदस्यों ने परिश्रम किया.

होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए प्लास्टिक का उपयोग कम कर प्रकृति अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया. इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, कानून, आदिवासी

समाज के अधिकार, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक विकास जैसे विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया. स्कूली विद्यार्थियों ने आदिवासी गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

बाधिन का बफर क्षेत्र में मुक्त विचरण



संवाददाता । वर्धा
समुद्रपुर तहसील के गिरड-खुसपार क्षेत्र से पिंजरे में कैद की गई बाधिन को करीब 15 दिन पहले सेलु तहसील के बोर व्याघ्र प्रकल्प के कोर क्षेत्र में निसर्गमुक्त किया गया था. कुछ दिनों तक कोर क्षेत्र में विचरण करने के बाद यह युवा बाधिन अब बोर के बफर क्षेत्र में पहुंच गई है. फिलहाल वह बफर क्षेत्र के सालई (कला) परिसर में मुक्त विचरण कर रही है. इसके चलते वन्यजीव प्रेमियों में चर्चा है कि युवा बाधिन को बोर का कोर क्षेत्र रास नहीं आया.

समुद्रपुर तहसील के गिरड-खुसपार क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले टीएफ-1 नामक बाधिन ने चार शावकों को जन्म दिया था. इनमें से एक शावक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद टीएफ-1 ने अपने शेष तीन शावकों को शिकार करने का प्रशिक्षण दिया. धीरे-धीरे ये तीनों शावक अपनी मां से अलग होने लगे और खेतों तक पहुंचकर पालतू पशुओं का शिकार

करने लगे. इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ गई थी. मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीएफ-1 के शावकों को पिंजराबंद करने के लिए अभियान चलाया गया. शुरुआत में वन विभाग ने एक-एक कर दो शावकों को बेहोश कर पिंजरे में बंद किया. इसके बाद जुलाई महीने में टीएफ-1 की तीसरी मादा शावक को भी बेहोश कर पिंजरे में कैद किया गया. कुछ दिनों तक निगरानी में रखने के बाद इस युवा बाधिन को निसर्गमुक्त करने का निर्णय लिया गया. इसके बाद करीब 15 दिन पहले उसे बोर व्याघ्र प्रकल्प के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया. निसर्गमुक्त किए जाने के बाद शुरुआती दिनों में बाधिन की गतिविधियां बोर के कोर क्षेत्र तक ही सीमित थीं. इसके बाद उसने कोर क्षेत्र छोड़कर सीधे बफर क्षेत्र में प्रवेश किया. वर्तमान में वह बोर व्याघ्र प्रकल्प के बफर क्षेत्र में आने वाले सालई (कला) परिसर में घूम रही है.

खुली आश्रमशालाओं की भयावह सच्चाई

छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़, विभाग की लापरवाही कटघरे में

संवाददाता । गडचिरोली
गडचिरोली जिले के जपतलाई स्थित अनुदानित आश्रमशाला में तीन मासूम छात्राओं की मृत्यु ने पूरे जिले को झकझोर दिया है. यह केवल एक दुःखद घटना नहीं, बल्कि आदिवासी छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति वर्षों से बरती जा रही गंभीर लापरवाही का भयावह उदाहरण है. इस घटना ने आदिवासी विकास विभाग, प्रकल्प कार्यालय, निरीक्षण तंत्र और आश्रमशाला प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कठोर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. आश्रमशालाओं का नियमित निरीक्षण होने का दावा सरकारी रिपोर्टों में दिखाई देता है. निरीक्षक पेयजल, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और छात्रावासों की स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजते हैं. लेकिन वास्तविक स्थिति देखकर यह सवाल उठ रहा है कि, क्या यह रिपोर्ट सचमुच जमीनी हकीकत को दर्शाती हैं? अधिकांश रिपोर्ट 'संतोषजनक' बताई जाती है, जिसके कारण स्कूल संचालकों पर कार्रवाई नहीं होती. परिणामस्वरूप कमियां जस की तस बनी रहती हैं और प्रशासन किसी बड़ी घटना के बाद ही जागता है. गडचिरोली जिले में 100 से अधिक आश्रमशालाएं हैं.

जिले में यह चर्चा नई नहीं है कि, कुछ आश्रमशालाएं प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों या



पूर्व पदाधिकारियों से जुड़ी हैं. ऐसे में क्या प्रशासन कठोर कार्रवाई करने से बचता है. यह सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है. शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर वे केवल अनुदान आधारित व्यवस्था बनकर रह गए हैं. दूरदराज क्षेत्रों की कई आश्रमशालाओं में शिक्षकों के पद रिक्त हैं. उपलब्ध शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ है. कुछ जगहों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय केवल परीक्षा परिणाम बनाए रखने पर जोर दिया जाता है. दसवीं और बारहवीं के परिणामों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के कारण गलत तरीकों के इस्तेमाल की शिकायतें भी गंभीर हैं. दूध, अंडे, केले और मांस जैसे पोषण आहार का रिकार्ड में उल्लेख होता है, लेकिन क्या यह सामग्री पूरी मात्रा में छात्रों तक पहुंचती है, इस पर प्रभावी निगरानी नहीं है.

छात्रों को लैपटॉप वितरित



संवाददाता / हिंणघाट
कृषि उपज बाजार समिति, हिंणघाट की ओर से नीलामी शेड का भूमिपूजन, बैल की मृत्यु एवं आग से प्रभावित परिवारों को चेक वितरण, विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण, जिला परिषद स्कूलों को सीलिंग फैन तथा डिजिटल इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल वितरण सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने की. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जबकि विधायक समीर कुणवार प्रमुख रूप से उपस्थित थे. सभापति एड. सुधीर कोठारी ने प्रस्तावना में बाजार समिति की सुविधाओं, किसान हित की योजनाओं और विभिन्न उपक्रमों की जानकारी दी. हिंणघाट कृषि उपज बाजार समिति ने अपनी कार्यक्षमता के दम पर राज्य की 305 कृषि उपज बाजार समितियों में प्रथम क्रमांक का पुरस्कार प्राप्त किया है. बाजार समिति ने आरुड लाभ लगातार बढ़ रहा है और किसानों को अधिक से अधिक

सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं. ऐसी जानकारी सभापति एड. कोठारी ने दी. बाजार समिति के शीतगृह के लिए जिला नियोजन समिति के माध्यम से 2 करोड़ रुपये का निधि उपलब्ध कराने की मांग विधायक समीर कुणवार ने की. साथ ही 7,200 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का कार्य सरकारी स्तर पर सहायता मिलने पर जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा भी बताया गया.

इस अवसर पर ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने हिंणघाट कृषि उपज बाजार समिति के कार्यों की सराहना की. सहकार क्षेत्र की कई संस्थाओं के प्रति विश्वास का संकट पैदा होने के बावजूद विदर्भ जैसे क्षेत्र में बाजार समिति का राज्य की सर्वश्रेष्ठ मंडियों में स्थान बनाना गर्व की बात है, ऐसा उन्होंने कहा. किसान भवन, विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूलों को सुविधाएं और विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के माध्यम से बाजार समिति ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ऐसा मंत्री गोरे ने कहा.

चामोर्शी तहसील में रोपाई में आएगी गति, फसलों को मिलेगी संजीवनी

अंततः कन्नमवार जलाशय से छोड़ा पानी

संवाददाता । गडचिरोली
विगत कुछ दिनों से बारिश विलुप्त होने से चामाशी तहसील में धान रोपाई के कार्य प्रलंबित थे, वहीं खेतों का पानी सुखने से किसान संकट में आए थे. ऐसे में चामोर्शी तहसील के रेगडी में स्थित कन्नमवार जलाशय से पानी छोड़ने की मांग हो रही थी. जिससे जलपूजन करते हुए कन्नमवार जलाशय से पानी छोड़ा गया. पानी छोड़े जाने से चामोर्शी तहसील में रोपाई के कार्यों में गति आनेवाली है. वहीं मुरझाती फसलों को भी इससे संजीवनी मिलनेवाली है. बीते कुछ दिनों से बारिश विलुप्त

हुई है, वहीं आगामी कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान नहीं होने के चलते चामोर्शी तहसील में खरीफ सीजन में धान रोपाई के कार्य लंबित हो रहे थे.

जिससे संकट से घिरे किसानों ने निरंतर प्रयास कर विधायक डा. मिलिंद नरोटे से रेगडी में स्थित कन्नमवार जलाशय का पानी छोड़ने की मांग की थी. इसके साथ ही तहसील के पानी उपयोग संस्थाओं ने भी दीना सिंचाई उपविभाग, चामोर्शी की ओर प्रयास किया था. किसानों के इस समस्या की तत्काल सूध लेते हुए विधायक डा नरोटे ने सिंचाई



विभाग को पानी छोड़ने के निर्देश दिए. इसके तहत 10 अगस्त को शाम के दौरान विधिवत जलपूजन

तथा गेट का पूजन कर कन्नमवार जलाशय से सिंचाई हेतु पानी छोड़ा गया. जिससे तहसील के किसानों

घायल 3 छात्राओं से मिले विधायक मसराम



संवाददाता / देसाईगंज
जिले की धानोरा तहसील अंतर्गत आने वाले जपतलाई आश्रमशाला की 6 छात्राओं को

रविवार की रात सर्पदंश होकर 3 छात्राओं की मृत्यु हो गयी. वहीं 3 छात्राएं घायल हो गयी थी. जिन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती

स्वास्थ्य संदर्भ में की गई पूछताछ

कराया गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही आरमोरी विस क्षेत्र के विधायक रामदास मसराम तत्काल गडचिरोली के जिला अस्पताल में पहुंचकर घायल छात्रों की भेट लेकर उनके स्वास्थ्य संदर्भ में पूछताछ की. साथ ही डाक्टरों को उचित उपचार करने की सूचना दी है. रविवार की रात जतपलाई गांव स्थित अनुदानित आश्रमशाला में फर्श पर सो रही 6 छात्राओं को एक

विषैले सांप ने डंस लिया. इस घटना में सुष्मिता सरोज मंडल (14), दीपिका एतवा लकडा (12) और अनुगजुराम कोरेटी (8) की मृत्यु हो गयी. वहीं दीपिका बिटलूरसाय मड़ावी (11), समृद्धि सुरेश नैताम (14) और कविता राजकुमार किरंगा (12) यह छात्राएं घायल होकर उन्हें उपचार के लिये गडचिरोली के जिला अस्पताल में रेफर किया गया.

अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी

जनसंवाद कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता वानखेड़े ने रखे अपने विचार

संवाददाता / गडचिरोली
स्वयं के हक तथा अस्तित्व की लड़ाई अन्य दूसरा आकर नहीं लड़ेगा, वह लड़ाई स्वयं को लड़नी पड़ेगी. अपने प्रश्नों को लेकर संगठित होकर आवाज उठाना आवश्यक है, ऐसा कथन सामाजिक कार्यकर्ता अशोक वानखेड़े ने किया.

गडचिरोली जिले के किसान, मजदूर, आदिवासी, युवक, महिला तथा आम नागरिकों के विभिन्न प्रश्नों पर जनसंवाद करने के लिए शुरु किए गए 'चरखे के पास चर्चा' इस कार्यक्रम के दूसरे दिन उन्होंने नागरिकों से संवाद करते हुए बोल रहे थे.



इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का संदर्भ देते हुए कहा कि, अन्याय के खिलाफ लड़ाई अहिंसा के मार्ग तथा लोकतंत्र के माध्यम से लड़नी चाहिए.

संविधान ने नागरिकों को दिए अधिकार केवल मांगने से मिलेंगे, ऐसा नहीं है. तो उन अधिकारों के लिए जागरूक रहकर लोकतंत्र के मार्ग से संघर्ष करना पड़ेगा.

गडचिरोली जिले के विकास के प्रश्नों पर उन्होंने सरकार के नितियों पर टिप्पणी की. आज सरकार कौन चला रहा है, यह पूछने की नौबत आयी है. बड़े उद्योग समूह का सरकार के निति पर तिनता प्रभाव है, इसका विचार करना जरूरी है. ऐसी बात उन्होंने कही. गडचिरोली का विकास किस दिशा में करना चाहिए, इसका निर्णय गडचिरोली की जनता को लेना चाहिए.

स्थानीय नागरिक, किसान तथा आदिवासियों के हितों का विचार सर्वप्रथम होना चाहिए. ऐसी भूमिका उन्होंने रखी. गडचिरोली के नागरिकों के प्रश्नों पर प्रत्यक्ष निर्णय तथा ठोस कृति होना आवश्यक है. गडचिरोली के उपजाऊ खेत जमिन, प्राकृतिक साधनसंपदा, जंगल तथा स्थानीय नागरिकों के अधिकार इसका संरक्षण करते हुए विकास का समतोल बनाएं रखना आवश्यक है. विकास के नाम पर स्थानीय नागरिकों का अस्तित्व, आजिविका व हक खतरे में न आने पाए. ऐसी बात उन्होंने कही.

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव तथा जिला प्रभारी संदेश सिंगलकर, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाड़े, पूर्व जिल्पा उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुसुम आलाम, पार्षद अध्यक्ष

सतीश विधाते, दिवाकर निसार, प्रमोद भगत, राजेश ठाकुर, शंकरराव सालोडकर, समशेरखान पठाण, माधव गावड, राजेंद्र बुले, अनिल कोठारे, रवींद्र पाल, विजय लाड, विलास चिचधरे, उत्तम ठाकरे आदि उपस्थित थे.

संवाददाता / वर्धा
खातेदारों से प्राप्त राशि पतसंस्था में जमा नहीं कर करीब 36 लाख 25 हजार 850 रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है. श्री नवदुर्गानागरी सहकारी पतसंस्था में गठित पांच सदस्यीय जांच समिति की पड़ताल में यह मामला उजागर हुआ.

शिकायत के आधार पर वर्धा शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पतसंस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलभूषण विठ्ठल वसू की शिकायत पर भास्कर चरणदास लड़े, निवासी सिंदी (मेघे) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार, जून माह में खातेदारों द्वारा जमा की गई रकम में कमी पाए जाने के बाद कुछ खातों की जांच की गई. इस दौरान बड़ी वित्तीय विसंगतियां सामने

आई. मामले की जानकारी पतसंस्था के अध्यक्ष को दिए जाने के बाद 12 जून को तत्काल बैंक बुलाकर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई. समिति ने 16 जून को संचालक मंडल की बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. जांच में सामने आया कि संबंधित अभिकर्ता 23 अप्रैल 2020 से पतसंस्था में कार्यरत था. उसकी जिम्मेदारी विभिन्न खातेदारों से प्रतिदिन नकद राशि एकत्र कर उसे संस्था में जमा करना तथा पासबुक में इसकी प्रविष्टि करना थी.

हालांकि, 1 जनवरी 2026 से खातेदारों से प्राप्त राशि नियमित रूप से संस्था में जमा नहीं किए जाने की बात जांच में सामने आई. इसके बाद खातेदारों के पास जाकर पासबुक तथा संस्था के खातों की जांच की गई, जिसमें रकम में अंतर पाया गया.

शिवालयों में भगवान शिव की पूजा-अर्चना जारी, आकर्षक रूप से सजाए गए मंदिर

संवाददाता / गोंदिया
भारतीय हिंदू त्यौहारों, उत्सवों, देवी-देवताओं के पर्व बारहों माह आते हैं, जिनमें कुछ माह महत्वपूर्ण होते हैं. इसी क्रम में सावन माह का शिव आराधना के लिए अपना अलग ही महत्व है. इस माह में भोलेनाथ की आराधना श्रद्धापूर्वक की जाती है. इसके लिए जिले के सभी शिव मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है. सावन माह को भगवान शिवजी की आराधना के लिए विशेष माने जाने के कारण इस माह में पूरी श्रद्धा के साथ किए जाने वाला अनुष्ठान फलीभूत होता है. प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के पिंडकेपार शिवालय, ग्राम नागरा में विशाल प्राचीन शिव मंदिर, स्थानीय

शिव मंदिरों में दर्शनों के लिए लग रहा भक्तों का तांता

मरारटोली के श्री जागरुक हनुमान मंदिर, पिंडकेपार शिवालय, शिव धाम फुलचूर, संत लहरी आश्रम मध्यकाशी कामठा, गोंदिया से तिरोड़ा मार्ग पर गंगाझरी से केवल 5 किमी. की दूरी पर केरझिरा के भगवान शिव मंदिर, गोरेगांव तहसील में स्थित शिव मंदिरों में से एक मुख्य रूप से बोंडुंदा, पोंगेझरा शिव मंदिर, मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग पर हजारों वर्ष पुरातन जागृत शशिकरण देवस्थान, तिरोड़ा तहसील में विभिन्न स्थानों के साथ ही तिरोड़ा तहसील के पूर्व दिशा में स्थित इंदौरा/निमगांव स्थित दुधधाट, तिरोड़ा



तहसील के चोरखमारा का शिव मंदिर, शिवमंदिर,, नागमंदिर खडकी, खडकी के आंबेतालाब स्थित नागमंदिर व शिवमंदिर, डोंगरगांव शिवमंदिर,

सावन में शिवजी की विशेष पूजा

पौराणिक कथा के अनुसार, सावन माह में समुद्र मंथन हुआ था. इस मंथन से 14 रत्न निकले थे. इनमें से 13 रत्नों को देवताओं एवं राक्षसों में बांटा गया. जबकि मंथन से प्राप्त विष को शिवजी पी गए और उसे अपने कंठ में संग्रहित कर लिया. विष के कारण गर्मी और संताप उत्पन्न हुआ. जिसे कम करने के लिए सभी देवताओं ने जल और अपने पास मौजूद अन्य चीजे शिवजी को अर्पित की. यहीं वजह है कि सावन में शिवजी का जल के अलावा दूध, दही, शहद आदि कई चीजों का मिश्रण कर अभिषेक किया जाता है. उल्लेखनीय है कि भगवान शिवजी की पूजा में 56 भोग नहीं लगाए जाते हैं.

श्री त्रिलोकेश्वर धाम, हलबीटोला में अर्धनारेश्वरालय मंदिर, आमगांव के महाकाली मंदिर परिसर में स्थित बाबा भोलेनाथ का मंदिर के साथ ही आमगांव शहर परिसर के प्राचीन मंदिर में से एक

स्थित शिवालय सहित अनेक मंदिर में पूजा, अर्चना, अभिषेक आदि लगभग सभी शिवालयों में मराठी सावन मास पर भगवान शिवजी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों का सुबह से तांता लग रहा है. 'गंगाधराये, ओम नमः शिवाय' उद्घोष के साथ भक्तों ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिवजी का अभिषेक करने के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की जा रही है. हिंदू धर्म में सावन मास में भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है. प्रति सोमवार को जिले के सभी शिवालयों में भक्तों का मेला लगा रहा है. इस माह में भोलेनाथ की आराधना श्रद्धापूर्वक की जाती है.

१ ४७ करोड़ के सड़क निर्माण में नियोजन का देखा जा रहा अभाव



संवाददाता / अर्जुनी मोर
महाराष्ट्र राज्य आधारभूत सुविधा विकास महामंडल (एमएसआईडीसी) की ओर से शहर में करीब 147 करोड़ रु. की लागत से सड़क व नाली का निर्माण कार्य शुरू है. बिरसा मुंडा चौक से शहर के मध्यवर्ती हिस्से तक चल रहे इस प्रोजेक्ट में नाली निर्माण के नियोजन को लेकर नागरिकों ने गंभीर आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि सड़क को भविष्य में चौड़ा करने की संभावना को ध्यान में रखे बिना वर्तमान में सड़क से सटाकर नाली का निर्माण किया जा रहा है. परियोजना में सड़क की चौड़ाई करीब 7 मीटर है दोनों ओर 1-1 मीटर नाली तथा सड़क और नाली के बीच 1.5 मीटर शोल्डर प्रस्तावित है. नागरिकों का कहना है कि शहर में ग्राम पंचायत के समय से मौजूद नाली को ध्यान में रखते हुए निर्माण की योजना बनाई जानी चाहिए थी. पुरानी नाली की जगह का उपयोग करने के बजाय सड़क के किनारे नई नाली बनाने से सड़क के भविष्य में चौड़ाईकरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है.

नागरिकों ने विशेष रूप से बिरसा मुंडा चौक के नियोजन पर सवाल उठाए हैं. इस क्षेत्र में रेलवे

और ब्रिज की ढलान के कारण सड़क की उपलब्ध चौड़ाई पहले ही सीमित है. सड़क से सटाकर नाली बनाने से भविष्य में सड़क और अधिक संकरी होने की आशंका जताई जा रही है. नागरिकों के अनुसार इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है.

ज्ञापन देने के बाद नगरसेवक राधेश्याम भेंडारकर, मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनवाने, समाजसेवी महादेव सलामे, पूनाराम जगन्नाथे, बालू नेवारे, मंगेश भलावी, सुधीर राजत, नरेशगोडाने और जगदीश मेश्राम समेत नागरिकों ने परियोजना अधिकारी से चर्चा की. चर्चा के दौरान नागरिकों ने नाली निर्माण से भविष्य में होने वाली संभावित समस्याओं से अवगत कराया. बताया गया कि जब तक इस मामले का उचित समाधान नहीं निकलता, तब तक संबंधित कार्य बंद रखने पर सहमति बनी है. नागरिकों ने मांग की है कि 147 करोड़ रु. की इस बड़ी परियोजना में गुणवत्ता के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक एवं दूरदर्शी नियोजन किया जाए.

गालीगलौज कर किया नुकसान

संवाददाता / गोंदिया
गोरेगांव थाने के तहत कटंगी निवासी फियादी टेकेश्वर भरतलाल रहांगडाले (58) के भाई की पत्नी किराना दुकान पर थी. इस दौरान आरोपी मिलिंद भाऊराव शहारे (40) ने दुकान पर किराना सामग्री खरीदी किया. इस दौरान फियादी के भाई की पत्नी ने उसे पैसों की मांग की. आरोपी ने पैसे देने से मना कर दिया. फियादी ने उसे सामग्री के पैसों की मांग की. जिस पर आरोपी ने उसके साथ गालीगलौज कर धक्का-मुक्की की. साथ ही घर से रॉड लेकर आया व दुकान में खड़े एक हजार रु. कीमत के अंडे फोड़कर मारपीट करने की धमकी दी.

किसानों के ‘फार्मर आईडी’ अपडेट करने की मांग

विधायक विजय रहांगडाले ने राजस्व मंत्री से की त्वरित कार्रवाई की मांग

संवाददाता / तिरोड़ा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ‘फार्मर आईडी’ आवश्यक है। लेकिन वर्ष 2024 के बाद विरासत नामांतरण अथवा भूमि की खरीद-बिक्री के कारण स्वामित्व में परिवर्तन होने के बावजूद अनेक किसानों की फार्मर आईडी अभी तक अद्यतन नहीं हुई है। इससे पात्र किसान तकनीकी समस्या के कारण ऋणमुक्ति योजना के लाभ से वंचित होने की आशंका है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए तिरोड़ा-गोरेगांव



विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय भरतभाऊ रहांगडाले ने राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को निवेदन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2024 के

भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन के बाद सात-बारा अभिलेख एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। हालांकि, यदि फार्मर आईडी समय पर अपडेट नहीं होती है, तो किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से ऋणमुक्ति योजना के लिए भूमि अभिलेख और डिजिटल रिकॉर्ड में समानता होना आवश्यक है। विधायक रहांगडाले ने कहा कि ‘केवल प्रशासनिक अथवा तकनीकी त्रुटि के कारण कोई भी पात्र किसान

‘बैंकर बुक्स एविडेंस’ को राकां का समर्थन



सांसद जैन ने राज्यसभा में रखी बात

संवाददाता / गोंदिया
राज्यसभा में ‘बैंकर बुक्स एविडेंस बिल, 2026’ पर हुई चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की ओर से सांसद राजेंद्र जैन ने विधेयक का पूर्ण समर्थन किया. उन्होंने कहा कि कानूनों में समय के साथ बदलाव होना आवश्यक है. वर्ष 1881 का पुराना कानून आज के डिजिटल भारत और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है. अपने संबोधन में सांसद जैन ने कहा कि वर्ष 1881 में जब मूल कानून बनाया गया था, तब कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. आज भारत डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत आज यूपीआई के माध्यम से होने वाले रियल टाइम डिजिटल लेन-देन में दुनिया में अग्रणी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में 221.67 अरब

महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है. इस नए विधेयक से न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता आएगी और बैंक अधिकारियों को लागू-बार-न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इससे बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों का भी महत्वपूर्ण समय बचेगा. बचने वाले समय का उपयोग मुद्रा लोन, पीएम एफ्लॉयमेंट गारंटी और कृषि अवसरचंचना (छ्द) जैसी सरकारी योजनाओं को अधिक तेजी से लागू करने में किया जा सकेगा.

तिरोड़ा में तालुकास्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन

पंजीयन और नियमावली को लेकर हुआ विस्तृत मार्गदर्शन

संवाददाता / तिरोड़ा
जिला खेल अधिकारी, गोंदिया, जिला खेल परिषद, गोंदिया तथा तालुका खेल अधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तिरोड़ा तालुकास्तरीय स्कूली खेल सभा मंगलवार, 11 अगस्त को तालुका खेल परिसर, तिरोड़ा में आयोजित की गई। सभा दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुई। इस अवसर पर तिरोड़ा तालुका क्षेत्र की विभिन्न



शालाओं के प्रधानाचार्य, खेल शिक्षक एवं सहायक शिक्षक बड़ी

आयोजित होने वाली विभिन्न तालुकास्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में खेल प्रतियोगिताओं के नियोजन एवं आयोजन, प्रतियोगिता नियमावली, खिलाड़ियों का पंजीयन, खेलों का समय-सारणी तथा शालाओं द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। संबंधित

अधिकारियों ने प्रतियोगिताओं का सुचारु एवं पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए शालाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

इसके साथ ही विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न खेल विधाओं में सहभागी बनाने उनकी प्रतिभा को उचित मंच उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित शिक्षकों से विद्यार्थियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने और नियमित

रूप से खेल गतिविधियों में सहभागी बनाने का आह्वान किया गया। सभा के माध्यम से तिरोड़ा तालुका की सभी शालाओं से आगामी शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित कर क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करने की अपील की गई। विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए शाला स्तर से ही प्रभावी प्रयास करने पर भी जोर दिया गया।